पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

वन नेशन, वन इलेक्शन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी पहल, देशहित में इसे शीघ्र लागू किया जाए–ए.के. शर्मा

बार–बार चुनाव से विकास की गति प्रभावित होती है, एक साथ चुनाव से देश की प्रगति को मिलेगी नई गति–श्री ए.के. शर्मा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को गति देगा वन नेशन, वन इलेक्शन–ए.के. शर्मा

वन नेशन वन इलेक्शन से चुनावी खर्च घटेगा, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

वन नेशन, वन इलेक्शन वन वोटर लिस्ट समय की आवश्यकता–ए.के. शर्मा

लखनऊ : 14 जुलाई, 2026

संयुक्त सदस्यीय समिति नई दिल्ली के सदस्यों के साथ आज स्थानीय होटल ताज में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार मंथन हुआ, जिसमें प्रदेश मंत्रि मण्डल के सदस्य मा0 उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री जयवीर सिंह, श्री धर्मपाल सिंह एवं पूर्व डिप्टी सीएम श्री दिनेश शर्मा उपस्थित रहे।

इस बैठक में प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने अपने सुझाव देते हुए कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और राष्ट्रहित में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है, जिसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी तथा विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के साथ वन वोटर लिस्ट का भी समर्थन किया।

श्री शर्मा ने कहा कि वे वर्ष 2021 से राजनीति में सक्रिय हैं और तब से अब तक लोकसभा, विधानसभा, पंचायत तथा नगर निकाय सहित पांच चुनाव देख चुके हैं। आगे वर्ष 2027 और 2029 में भी चुनाव होने हैं। इस प्रकार केवल आठ वर्षों में आठ चुनावों की स्थिति बन जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चुनाव से दो–तीन माह पहले पूरा प्रशासन चुनावी तैयारियों में व्यस्त हो जाता है, जिससे सामान्य प्रशासनिक एवं विकास

कार्यों की गति स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है। यही स्थिति चुनाव संपन्न होने के बाद भी कुछ समय तक बनी रहती है।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यदि वन नेशन, वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो चुनावों की आवृत्ति कम होगी, चुनावी खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी, सुरक्षा बलों की बार–बार तैनाती की आवश्यकता घटेगी, प्रशासन विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेगा तथा सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। इससे जनता को भी बेहतर और समयबद्ध सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है, उसे साकार करने के लिए प्रशासनिक दक्षता और विकास की निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। वन नेशन, वन इलेक्शन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त तथा विकासोन्मुख बनाएगा।

बैठक में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य सहित मंत्रिमंडल के उपस्थित सदस्यगण ने देश हित में इसे लागू करने का समर्थन किया। पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह देशहित में जरूरी है और ऐसे सुधारों पर सभी राजनीतिक दलों तथा समाज के सभी वर्गों को सकारात्मक सोच के साथ आगे आना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह व्यवस्था लागू होने से लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी।

सम्पर्क सूत्र– प्रवीण मालवीय

राघवेन्द्र / 04:40 PM